

पैन पॉवर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र



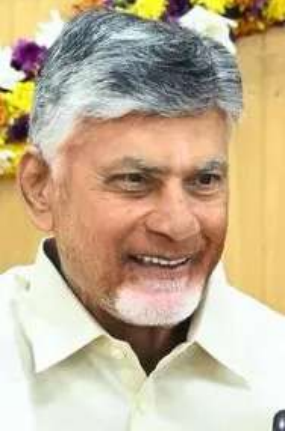
वर्ष - 1 अंक - 87

मंगलवार, अक्टूबर 13, 2026

विशाखापट्टनम संपादक: गंट्यादा अप्पाराव

पृष्ठों. 4मूल्य. 1रु

तिरुपति में 3,222 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम चंद्रबाबू ने किया शुभारंभ



(पैन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 12 अक्टूबर: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 3,222 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने अमरावती

स्थित राज्य सचिवालय से वक्तुअल माध्यम से इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2,750 करोड़ की लागत से प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पिलग्रिम टाउनशिप का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि तिरुपति की लागत से प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पिलग्रिम टाउनशिप का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि तिरुपति की लागत से प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पिलग्रिम टाउनशिप का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि तिरुपति की लागत से प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पिलग्रिम टाउनशिप का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाए।

परियोजनाओं का कार्य ऐसी एजेंसियों को सौंपा जाए जो केवल मुनाफा कमाने के बजाय भगवान की सेवा की भावना से काम करें।
तिरुपति में भी दिखे तिरुमला जैसा आध्यात्मिक वातावरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटेड पिलग्रिम टाउनशिप में भी तिरुमला जैसा पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरुपति की पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को ऐसा अनुभव होना चाहिए, मानो वह स्वर्ग में पहुंच गया हो। चंद्रबाबू ने कहा कि ऐसा वातावरण तैयार करना एक पुण्य कार्य होगा और इससे जुड़े सभी लोगों को आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने अधि

कारियों को तिरुपति से रेंगिगुटा तक के क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास के साथ एक स्वच्छ, हरित और भव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति भक्ति और सेवा भावना बढ़ाने के लिए विशेष अनुभव केंद्र स्थापित करने की बात कही। साथ ही गोशालाओं को ऐसे केंद्रों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया, जहां श्रद्धालु

गायों की सेवा कर सकें और उनके संरक्षण के महत्व को समझ सकें।
आध्यात्मिकता और तकनीक के समन्वय पर जोर
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना भी ईश्वर की आराधना का एक रूप है। भगवान से जुड़ने के लिए लोगों में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने जलाशयों और तालाबों को आपस में जोड़ने तथा उनके आसपास ऐसे पैदल मार्ग विकसित करने का सुझाव दिया, जहां लोग सुबह सुप्रभातम के भक्ति गीत सुनते हुए सैर कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक के समन्वय से तनावमुक्त और शांतिपूर्ण

वातावरण तैयार किया जा सकता है। उन्होंने तिरुपति में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चंद्रबाबू ने कहा कि तिरुमला की तरह तिरुपति में भी व्यापक हरियाली विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों का दृश्य लोगों में सकारात्मक और सुखद अनुभूति पैदा करता है। इस कार्यक्रम में टीटीडी के अध्यक्ष बी.आर. नायडू, कार्यकारी अधिकारी एम. रविचंद्र, टीटीडी बोर्ड के सदस्य, तिरुपति जिला कलेक्टर और तुडा के अधिकारी वक्तुअल माध्यम से शामिल हुए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 14 और 15 अक्टूबर को विजयवाड़ा का दौरा करेंगी



(पैन पॉवर न्यूज):

अमरावती: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 14 और 15 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह इंद्रकीलाद्रि पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध श्री कनक दुर्गा मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगी। इसके अलावा, विजयवाड़ा के पुन्नमि घाट पर आयोजित सरस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

14 अक्टूबर को कनक दुर्गा मंदिर में करेंगी दर्शन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 14 अक्टूबर को शाम 6:25 बजे गन्मवरम हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। वहां से वह विजयवाड़ा स्थित इंद्रकीलाद्रि पहाड़ी पर श्री कनक दुर्गा मंदिर जाएंगी और रात 7:20 बजे देवी कनक दुर्गा के दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण तथा प्रोटोकॉल संबंधी व्यवस्थाओं पर अधिकारी विशेष ध्यान दे रहे हैं।

15 अक्टूबर को सरस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल

राष्ट्रपति 15 अक्टूबर को विजयवाड़ा के पुन्नमि घाट पर आयोजित सरस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। इस अवसर पर वह स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं और लखपति दीदियों के साथ आयोजित भोज कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का मंच बनेगा। विजयवाड़ा का दो दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 15 अक्टूबर की दोपहर गन्मवरम हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की
इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद ने राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े सभी प्रोटोकॉल नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा या बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पहले से व्यापक योजना बनाकर आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, यातायात नियंत्रण, कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों के निर्धारण जैसे विषयों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

ch I h ;okvk dk e|r f l foy l ok dkfp x] M,- y{e;k vkb, , l vdkneh d l kFk l e>krk

(पैन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 12 अक्टूबर: आंध्र प्रदेश की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री सविता ने बताया कि बीसी कल्याण विभाग ने बेरोजगार पिछड़ा वर्ग (बीसी) के युवाओं को मुफ्त सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग प्रदान करने के लिए पी4 मॉडल के तहत डॉ. लक्ष्मैया आईएएस अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के विजन के अनुरूप पी4 मॉडल के तहत समझौता होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस समझौते के माध्यम से बीसी स्टडी सर्किलों के तत्वावधान में बेरोजगार बीसी युवाओं को मुफ्त सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सिविल सेवाओं में चयनित होने का सपना देखने वाले युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। मंत्री सविता ने कहा कि डॉ. लक्ष्मैया

आईएएस अकादमी बेरोजगार बीसी युवाओं को मुफ्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगी। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ और अनुभवी शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस समझौते से बीसी युवाओं को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का लक्ष्य बीसी युवाओं को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचाना है। मंत्री ने कहा कि गठबंधन

सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही बीसी स्टडी सर्किलों के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जा रही है।
दो वर्षों में 200 अभ्यर्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण
मंत्री सविता ने बताया कि पिछले दो वर्षों में दो बैचों के माध्यम से कुल 200 अभ्यर्थियों को मुफ्त सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग प्रदान की गई है। वर्ष 2024-25 में पहले बैच के तहत एनटीआर जिले के विजयवाड़ा स्थित गोल्लापुडी के

बीसी भवन में संचालित आंध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा स्टडी सर्किल के माध्यम से बीसी, एससी और एसटी वर्गों के 100 अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 में दूसरे बैच के तहत बीसी, एससी और एसटी वर्गों के अन्य 100 अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की गई।

प्रशिक्षण से मिले सकारात्मक परिणाम
मंत्री सविता ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 21 अभ्यर्थियों ने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) की ग्रुप-II प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की, जबकि 12 अभ्यर्थी ग्रुप-II मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए। इसके अतिरिक्त, 44 अभ्यर्थियों का बैंकों, पुलिस विभाग, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और वन विभाग के विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से चयन हुआ।

‘सुप्रीम कोर्ट को राजनीति में न घसीटें’

एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख

> याचिका दाखिल, राहुल समेत 11 नेताओं के नाम

> विरोध-प्रदर्शनों पर बोले सीजेआई सूर्यकांत
> कामकाज बाधित न करने की अपील

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों की राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए और किसी भी चीज से इसके कामकाज या वकीलों और याचिकाकर्ताओं की आवाजाही में बाधा नहीं आनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी और प्रदीप राय ने वकीलों की हिरासत से संबंधित याचिकाओं का जिक्र किया। नाडकर्णी ने एक वकील द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया, जबकि



एससीबीए अध्यक्ष राय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका का जिक्र किया। एससीबीए की याचिका वकीलों की हिरासत और इंटरनेट निलंबन से संबंधित है। मंगलवार को इन मुद्दों पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

‘मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत, आपके पत्र में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराता है।’

सीजेआई सूर्य कांत

ये सभी लोकतांत्रिक गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में तो होनी ही चाहिए। नाडकर्णी ने कहा कि उनकी याचिका एक स्वतंत्र वकील की ओर से है, जिसमें वास्तविक कठिनाइयों को बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए-सीजेआई
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘मैंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें किसी भी तरह से घसीटा नहीं जाना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करें।
अदालत के कामकाज में, वकीलों की आवाजाही में, अदालत के कर्मचारियों की आवाजाही में, वादियों की आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए।’ राय ने कहा, ‘मैंने इस संबंध में एक बयान दिया है कि उन्हें अदालत को इस सब में नहीं घसीटना चाहिए और उन्हें भी जिम्मेदार राजनीतिक दल होना चाहिए।’ बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी मार्च का आह्वान किया है। ऐसे में सीजेआई की टिप्पणियां काफी अहम हो जाती हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने के वक्त मांगा था। हालांकि, सीजेआई ने इनकार कर दिया। >14

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी टीम ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के आरोप उठाए गए हैं। इस मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।



मल्लिकार्जुन खरेगे, तृणमूल कांग्रेस के सींगार राय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हैं। इनके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, मकपा के एम. ए. बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, झारवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई. टी. मोहम्मद बशीर के नाम भी याचिका में हैं। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए हैं। साथ ही, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है।

जंतर-मंतर अब नहीं होगा निर्धारित प्रदर्शन स्थल

दिल्ली पुलिस ने तय किए रामलीला मैदान समेत तीन नए स्थान
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। दिल्ली पुलिस ने धरना-प्रदर्शन के लिए नई गाइडलाइस जारी की हैं। नए आदेश के तहत जंतर-मंतर अब आधिकारिक प्रदर्शन स्थल नहीं रहेगा और इसे डीनोटिफाइड कर दिया गया है। रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए तय किया गया है। यह बदलाव गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर एल&ओ/48/2026 के तहत प्रदर्शन को लेकर नई गाइडलाइस जारी की हैं। यह फैसला गृह मंत्रालय की एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। गौर करने वाली बात है कि जंतर-मंतर से पहले दिल्ली में आधिकारिक धरना स्थल बोट हब था। बाद में बोट हब को हटाकर जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल बनाया गया था। नए आदेश के तहत रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन स्थलों के रूप में नामित किया गया है।

‘सरकारी गवाह बन जाओ, तुमने अपराध किया है’

> राहुल गांधी का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मौसेज

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार के पास गवाह बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे।



इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कोई से कोई

अपराधी नहीं हो। तुमने गलती की है। तुम इस गलती के पीछे का मुख्य दिमाग नहीं हो।’ हालांकि राहुल ने उन मौसेज के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी, जिसका वह दावा कर रहे थे।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा करके बड़ी राजनीतिक गलती कर रही है, क्योंकि इससे विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग को लेकर अपने सवाल देश के सामने रखने का अवसर मिल रहा है।

केरलम विधानसभा : ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित

तिरुवनंतपुरम, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। केरलम विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनेल में बदलाव की मांग की गई।
मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव संशोधनों के साथ पारित हो गया। हालांकि तीन भाजपा सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोमवार को यह प्रस्ताव पेश किया। इसमें मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेसिव रिविजन’ (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई गई थी। इन अनियमितताओं में बिना किसी स्पष्ट नियम या पूर्व सूचना के योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात भी शामिल थी। केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने स्पेशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा केरलम विधानसभा ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के माध्यम से केरलम ने तीन स्पष्ट मांगें रखी हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को दूर किया जाए और गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर किए गए सभी पत्र मतदाताओं के मतदान के अधिकार तुरंत बहाल किए जाएं।

संपादकीय

आईटी पेशेवरों को झटका..

ट्रंप की चुनावी ‘चाल’

अमेरिकियों की नौकरियां छीनने और एच–1बी वीजा नियमों का दुरुपयोग करने सहित विभिन्न आरोपों के आधार पर अमेरिकी सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट और इंफोसिस समेत आठ दिग्गज आईटी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (व्हेट्ड) से इन कंपनियों को निर्लंबित करने का सनसनीखेज फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्लंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब इन कंपनियों से स्थायी श्रम प्रमाणन के नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही पहले से लंबित आवेदनों की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। हालांकि इस फैसले से अमेरिका को जितना लाभ होगा, उससे कहीं अधिक नुकसान होने की आशंका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार–बार ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नारा दोहराते हैं। वे अमेरिकियों के बीच दूसरे देशों से आने वाले कुशल पेशेवरों के प्रति नाराजगी और विरोध की भावना को बढ़ावा देते रहते हैं। अब लिए गए फैसले भी आगामी चुनावों में वोट बैंक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रेरित दिखाई देते हैं। इनके पीछे कोई ठोस आर्थिक उद्देश्य नजर नहीं आता।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा अमेरिका आने वाले वीजाधारकों को ‘बंधुआ मजदूरों’ की तरह प्रस्तुत करना अमेरिका के अपने इतिहास की अनदेखी करना है। कई पीढ़ियों के प्रवासियों ने अपने कठिन परिश्रम, व्यावसायिक कौशल और नए आविष्कारों के माध्यम से अमेरिका के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतीत में भारतीयों को मॉरीशस, फिजी, कैरेबियाई द्वीपों और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अनुबंधित मजदूरों के रूप में काम करते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। भारत ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के लिए लाभकारी इस क्षेत्र में अमेरिका द्वारा उठाए गए कुछ कदम उनके साझा उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं। भारत ने चेतावनी दी है कि भारतीय आईटी पेशेवरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई दोनों देशों के संबंधों और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रमुख आईटी कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर व्यापक स्तर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन अपनी नीति बदलने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। अमेरिकी श्रम सचिव के अनुसार, वर्ष 2009 से इन आठ कंपनियों ने लगभग 30 लाख विदेशी कर्मचारियों के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। इन कंपनियों को 2.30 लाख से अधिक एच–1बी वीजा स्वीकृतियां और एक लाख से अधिक स्थायी श्रम प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। श्रम सचिव ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों की भर्ती प्रक्रियाओं के कारण लाखों स्थानीय अमेरिकी नागरिकों को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ा। अब अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की उम्मीद लगाए बैठे हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवरों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। नियोजका द्वारा प्रायोजित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में ‘पर्म’ अमतौर पर पहला महत्वपूर्ण चरण होता है। अब इसी प्रक्रिया पर प्रतिबंध ा लगाए जाने से प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों में काम करते हुए अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देखने वाले पेशेवरों को बड़ा झटका लगा है। स्थायी श्रम प्रमाणन की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के प्रशासन ने परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू की थी। इसके माध्यम से अमेरिकी कंपनियों विदेशी कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए प्रायोजित कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिकी श्रम विभाग को यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि संबंधि त नौकरी के लिए योग्य और इच्छुक अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति से समान प्रकार के कार्य करने वाले स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और कार्य परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दूसरी ओर, एच–1बी एक अस्थायी कार्य वीजा है। इसके तहत विदेशी पेशेवरों को सामान्यतः अधिकतम छह वर्षों तक अमेरिका में काम करने और रहने की अनुमति मिलती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। इस प्रकार अमेरिका में एच–1बी वीजा पर काम कर रहे और स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के लिए अपनी कंपनियों के प्रायोजन पर निर्भर हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को गंभीर झटका लगा है। इस निर्लंबन के कारण उनके मौजूदा एच–1बी वीजा स्वतः रद्द नहीं होंगे, लेकिन ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की दिशा में उनकी प्रगति बाधित हो सकती है।

स्थायी निवास की संभावना सीमित होने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशों से प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना और उन्हें लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना कठिन हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय पेशेवरों को लंबे समय तक अस्थायी वीजा पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। इससे उनके करियर और अमेरिका में स्थायी रूप से बसने की योजनाओं को लेकर अनिश्चितता बढ़ेगी। ट्रंप प्रशासन ने यह तर्क देते हुए कड़े फैसले लिए हैं कि विदेशी नागरिकों को वीजा देने से अमेरिकियों के साथ अन्याय हो रहा है और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। इस संदर्भ में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा माइक्रोसॉफ्ट पर लगाए गए आरोप उल्लेखनीय हैं। वेंस ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।

इसी दौरान कंपनी ने 6,000 से अधिक एच–1बी वीजा स्वीकृ तियां प्राप्त कीं और 3,682 पर्म आवेदन प्रस्तुत किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें लगभग 1,000 पद ऐसे थे जिन पर पहले नौकरी से निकाले गए अमेरिकी कर्मचारी काम कर रहे थे। वेंस ने कंपनियों पर यह भी आरोप लगाया कि वे नौकरियों के विज्ञापन सीमित स्तर पर प्रकाशित करती हैं और बाद में योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने येल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कैलिफोर्निया इस्टीमेट्ड ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) सहित नौ प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा शोधार्थियों और शोधकर्ताओं के वेतन तथा रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इन घटनाक्रमों ने अमेरिका की आव्रजन और रोजगार नीतियों की दिशा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के नाम पर लागू की जा रही ऐसी नीतियां अंततः अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की अमेरिका की क्षमता को कमजोर कर सकती हैं।

जेन जी की हुंकार से सत्ता में हड़कंप!

“क्या मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना चाहिए?” दिल्ली में शनिवार को जंतर–मंतर के पास कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी थी।

कॉंकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने आने वाले लोगों को रोकने के लिए दिल्ली में किए गए व्यापक इंतजामों पर टिप्पणी करते हुए सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी हो। दिल्ली की वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने शनिवार को एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर कहा, “मैंने अपने जीवन में दिल्ली की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। आपातकाल के दौरान भी ऐसे हालात नहीं थे।” दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। पूरी दिल्ली में लगभग 35 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर सवाल उठाया, “आखिर इतनी अफरातफरी क्यों? कुछ लोगों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी जनता को परेशान करना क्या उचित है? क्या मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना चाहिए?” हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, विशेषकर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां विवादों का विषय बन रही हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉंकरोच से की थी। उसी टिप्पणी की व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई कॉंकरोच जनता पार्टी आज केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यह संगठन अब केवल युवाओं की शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याओं तक सीमित

नहीं रहा है। देश में लोकतंत्र के सामने उत्पन्न खतरों और बुनियादी मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए यह केंद्र सरकार को मुश्किल में डालने वाली एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सड़क आंदोलनों को महत्वहीन बताने का प्रयास कर रहे हैं।

उनका कहना है कि सड़कों पर होने वाले ऐसे आंदोलनों से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे कितने ही आंदोलन पहले भी देखे जा चुके हैं। वे दावा करते हैं कि ये युवा नेता भी हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार की तरह एक दिन राजनीतिक परिदृ श्य से गायब हो जाएंगे।

अब उसी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों की तुलना मक्खियों से की है। देखना होगा कि यह टिप्पणी आगे किस प्रकार के घटनाक्रम को जन्म देती है। यदि अब कोई ‘मक्खी जनता पार्टी’ भी अस्तित्व में आकर कॉंकरोच जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हो जाए, तो अपनी कुर्सियां बचाने और दिल्ली की घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए एनडीए सरकार ने पाने कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी।

फिलहाल इस संभावना को छोड़ दें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार शनिवार को जंतर–मंतर पर प्रस्तावित कॉंकरोच जनता पार्टी के विरोध ा प्रदर्शन को विफल करने के लिए इतनी दृढ़ क्यों थी? कॉंकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी, विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को रद्द करने तथा चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से संरक्षण देने वाले 2023 के संशोधनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है।

इसी आंदोलन के तहत शनिवार को जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। यदि एसआईआर प्रक्रिया



के तहत 13 करोड़ लोगों का मताधिकार समाप्त कर दिया गया है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त देश को यह बताने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं?

प्रसिद्ध पत्रकार राजदीप सरदेसाई द्वारा सूचना का अधि कार अधिनियम के तहत बार–बार जानकारों मांगे जाने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर यह जवाब क्यों दिया कि उसके पास संबंधि त विवरण उपलब्ध नहीं हैं?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर देश की जनता की शंकाओं का समाधान करना चाहिए। इसके बजाय भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के एक अन्य नेता संबित पात्रा से संदिग्ध आंकड़े पेश करवाकर जनार्थी हमला करता जा रहा है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए चुनाव आयुक्तों को संरक्षण नहीं दिया था? क्या उनकी सेवाओं के बदले उन्हें बड़े–बड़े पद नहीं दिए गए थे? इस तरह के प्रत्यारोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर देना और मूल सवालों का जवाब दिए बिना चले जाना क्या हास्यास्पद नहीं है?

कुछ भाजपा नेता इससे भी आगे

बढ़कर मौजूदा परिस्थितियों को लोकतंत्र और अराजकता के बीच युद्ध के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वे मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए जेन जी द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष को अराजकता का नाम देने का असफल प्रयास कर रहे हैं।

वहीं कुछ अन्य भाजपा नेता टेलीविजन बहसों में उपदेश देते हैं कि कानून बनाना या उनमें संशोधन करना संसद का काम है, सड़कों का नहीं।

इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और ज्ञानेश कुमार के उदासीन रवैये को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर भी असहमति दिखाई दे रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री विराग पासवान की टिप्पणियां इसी ओर संकेत करती हैं। दूसरी ओर, एनडीए के एक अन्य सहयोगी और आंध्र ा प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ज्ञानेश कुमार के गुणों की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। उनके इस रवैये को देखकर जेन जी हैरान हैं। इस बीच तेलुगु मीडिया के कुछ प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को दिनभर यह प्रचार किया कि इन घटनाक्रमों से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे अधिक राजनीतिक अनुभव रखने वाले चंद्रबाबू नायडू

‘वोट’ बचाने के आंदोलन में अखिर कहां हैं सुपरस्टार?

लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे, लहलुहान हो रहे युवा या पर्दे के पीछे खामोशी से बैठे सुपरस्टारकृआखिर असली हीरो कौन हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र की प्राणशक्ति संविधा न है। संविधान की आत्मा जनता की संप्रभुता है। और इस संप्रभुता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मतदान का अधिकार है। जब इसी मताधिकार की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हों, देशभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हों और युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही हो, तब एक सवाल बार–बार हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर असली हीरो कौन हैं? जनता के अधिकारों के लिए खड़े वाले युवा या फिर रुपहले पर्दे पर जनता के लिए संघर्ष करने वाले किंदरार निभाकर वास्तविक जीवन में खामोश रहने वाले सुपरस्टार? वोट केवल एक निशान नहीं है। यह नागरिक के अस्तित्व को संविधान द्वारा प्रदान की गई मान्यता है। यह शासकों को चुनने का अधिकार, सत्ता से सवाल करने की ताकत और पसंद न आने वाली सरकार को बदलने का अवसर है।

ऐसे महत्वपूर्ण मताधिकार से जुड़ी मतदाता सुचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने देशभर में गंभीर बहस छेड़ दी है। विभिन्न राज्यों की मसौदा मतदाता सुचियों से करोड़ों नाम गायब होने या शामिल नहीं किए जाने को लेकर संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। इनमें मृत व्यक्तियों, दूसरे स्थानों पर पलायन कर चुके लोगों और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? कितने पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सुचियों से हट गए हैं? इन सवालों के पारदर्शी जवाब मिलना

लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इन घटनाक्रमों के बीच दिल्ली के जंतर–मंतर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर युवा, छात्र और नागरिक समाज के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेहा बोरा जैसी युवा नेता, जेन जी के कार्यकर्ता और कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से जुड़े अभिजीत दीपके जैसे लोग लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिरासत में लिए जाने, पुलिस की लाठियां खाने, घायल होने और गिरफ्तारियों का सामना करने के बावजूद वे अपना संघर्ष छोड़ने या अपने सवाल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इन युवाओं के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति नहीं है। वे सैकड़ों करोड़ रुपये का पारिश्रमिक नहीं लेते। उनके पास विशाल प्रशंसक संगठन नहीं हैं।

आलीशान बैनैटी वैन और सुरक्षाकर्मियों की फौज भी नहीं हैं। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज है जो इन सब से कहीं अधिक मूल्यवान हैकूलोकतंत्र के लिए खड़े होने का साहस। उन्हें नहीं मालूम कि उनका भविष्य क्या होगा, फिर भी वे सवाल उठाने का साहस रखते हैं। वे केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। इसीलिए आज सड़कों पर खड़े ये युवा ही असली हीरो हैं। ये रील हीरो नहीं, रियल हीरो हैं! जनता के प्यार और समर्थन से लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचकर करोड़ों रुपये कमाने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार आखिर कहां हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे दिग्गज अभिनेता इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं?

दक्षिण भारत में महेश बाबू, राम चरण, जूनियर एनटीआर, तमिल सिन्हा के सूर्या और मलयालम तथा कन्नड़ फिल्म उद्योगों के प्रमुख अभिनेता क्या कर रहे हैं? ये सवाल उनके प्रति किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं पूछे जा रहे हैं। ये सवाल उन लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें हीरो बनाया। उनकी फिल्मों के टिकट किसने खरीदे? सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारों में कौन खड़ा रहा? उनके पोस्टरों पर दूध से अभिषेक किसने किया? उनकी सफलताओं को अपनी सफलता मानकर जश्न किसने मनाया? आम जनता ने ही तो!

फिर जब उसी जनता के मतदान के अधिकार को लेकर देशभर में चर्चा हो रही हो, लोकतंत्र के भविष्य पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हों और युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, तब इन लोकप्रिय हस्तियों से कम से कम एकजुटता का बयान देने की उम्मीद करना क्या गलत है? हो सकता है कि वे सड़कों पर न उतर सकें। संभव है कि वे राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना पसंद न करते हों। लेकिन क्या लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के प्रति एकजुटता व्यक्त करने वाला एक छोट–सा बयान देना भी संभव नहीं है?

क्या घायल हो रहे युवाओं के प्रति मानवीय संवेदना और चिंता व्यक्त करना भी इतना कठिन है? उनकी चुप्पी के कारण हमें नहीं मालूम। यह डर है, पेशेवर सीमाएं हैं या उनका व्यक्तिगत निर्णयकूइस बारे में अनुमान लगाकर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन जनता के प्यार और समर्थन से व्यापक सामाजिक प्रभाव हासिल करने वाली हस्तियां से उनकी सामाजिक जिम्मेदारी

के बारे में सवाल पूछने का अधि कार जनता को अवश्य है। फिल्मों में हीरो व्यवस्था पर सवाल उठाता है। मजदूरों के पक्ष में खड़ा होता है। गरीबों के लिए लड़ता है। अन्याय का विरोध करता है। सत्ता को चुनौती देता है। ऐसे दृश्यों पर सिनेमाघर तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठते हैं। लेकिन जब वास्तविक जीवन में जनता अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाती है और वही हीरो खामोश रहते हैं, तो दर्शकों को यह विरोधाभास समझ में आए बिना नहीं रह सकता। उनमें नाराजगी पैदा होना भी स्वाभाविक है। हालांकि यह कहना भी सही नहीं होगा कि पूरा फिल्म उद्योग खामोश है। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी जैसी प्रमुख हस्तियों ने विरोध प्रदर्शनों को समर्थन दिया है। शबाना आजमी ने कथित तौर पर जंतर–मंतर पर नेहा बोरा के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के साथ मुंबई में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया।

विशाल ददलानी, विशाल भारद्वाज और अन्य कलाकारों के भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की खबरें सामने आई हैं। इन सभी की सराहना की जानी चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में बोले के लिए आगे आने वाले प्रत्येक कलाकार का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही देश के सभी फिल्म उद्योगों से कहीं अधिक व्यापक प्रतिक्रिया की अपेक्षा भी की जानी चाहिए। बॉलीवुड से टॉलीवुड तक, कॉलीवुड से मॉलिवुड तक, कन्नड़ फिल्म उद्योग सहित अन्य भाषाओं की फिल्मी दुनिया को भी लोकतंत्र पर चल रही बहस में जिम्मेदारी के साथ भाग लेना चाहिए।

केवल अभिनेता और अभिनेत्रियां ही नहीं, बल्कि निर्देशक, लेखक,

आनन–फानन में दिल्ली पहुंचे। इन खबरों के अनुसार, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर लगभग डेढ़ घंटे बिताए। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार कॉंकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से इतनी भयभीत क्यों है? भाजपा शासित महाराष्ट्र के मुंबई में इसी संगठन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कोई हिंसा हुई थी? यदि वहां हिंसा नहीं हुई, तो दिल्ली में हिंसा होने की आशंका क्यों जताई जा रही है? इस संदर्भ में कॉंकरोच जनता पार्टी के पहले जंतर–मंतर आंदोलन की घटनाओं को याद करना आवश्यक है। उस समय अभिजीत दीपके विदेश से दिल्ली पहुंच रहे थे। उनके विमान के उतरते ही पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर उनका स्वागत किया और विरोध प्रदर्शन की अनुमति का पत्र स्वयं उन्हें सौंप दिया। क्या कुछ ही महीनों में वही अभिजीत दीपके सरकार के लिए विघटनकारी तत्व बन गए? शनिवार सुबह अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों आशुतोष रांका तथा सौरभ दास को विमान के भीतर ही गिरफ्तार क्यों किया गया?

कॉंकरोच जनता पार्टी के सह–संयोजक सौरभ दास ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा कि जिस सरकार के खिलाफ

विरोध प्रदर्शन करना है, उसी सरकार से अनुमति मांगने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा, “लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संबंधि त प्रशासन को केवल सूचना दी जाती है, ताकि वह आवश्यक एहतियाती इंतजाम कर सके।” सौरभ दास की बात पर विचार करें तो शायद इस देश की जनता को विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए भी एक नया आंदोलन चलाना पड़ेगा। देश के युवाओं की मांग के सामने झुककर वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मद्र प्रधान से इस्तीफा दिलाने वाली मोदी सरकार अब एक अधिकारी को पद से हटाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? कुछ बुद्धिजीवी यह तर्क दे रहे हैं कि इस्तीकों से क्या लाभ होगा? सरकार ज्ञानेश कुमार से भी इस्तीफा दिलवाकर पूरे विवाद से अपना पल्ला झाड़ सकती है। लेकिन सरकार के कदमों से स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा दिलवाना उतना आसान नहीं है, जितना धर्मद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाना था। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का धागा खींचने पर पूरा जाल खुल सकता है।

इसी प्रकार का साहस दिखाने वाले युवाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करना चाहिए। उनका संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहे, इसके लिए समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। फिल्म जगत से भी हमारी यही अपील है। जनता ने आपको स्टारडम दिया। बाजार दिया। नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा दी। अब लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित उसी जनता के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त कीजिए। अपनी आवाज जनता की आवाज से मिलाइए। क्योंकि रुपहले पर्दे पर हीरो बनना एक पेशा है। लेकिन जनता के कठिन समय में उसके साथ खड़ा होना एक मूल्य है, एक जिम्मेदारी है! रील हीरो पर्दे पर दिखाई देते हैं।रियल हीरो जनता के संघर्षों में दिखाई देते हैं। आज वे रियल हीरो हमारी सड़कों पर हैं। वे हमारे लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनके साहस को पहचानना, उनके अधिकारों का सम्मान करना और लोकतंत्र की रक्षा के प्रयासों को समर्थन देना हम सभी की जिम्मेदारी है। अंत में, उन लोगों से एक सवाल जिन्हें हम रुपहले पर्दे पर हीरो के रूप में देखते हैं। जनता आपके लिए खड़ी रही है। अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जनता के साथ कब खड़े होंगे? फिल्म समाप्त होने के बाद रुपहला पर्दा अंधेरे में डूब जाता है। किंदरार गायब हो जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र का संघर्ष समाप्त नहीं होता। उस संघर्ष में कौन जनता के साथ खड़ा हुआ और किसने एक सच्चे हीरो की तरह लड़ाई लड़ीकूइतिहास उन्हीं लोगों को याद रखेगा। वही असली हीरो हैं!

अराजकता से बाज आए कांग्रेस, वरना जो बचा है वह भी गंवा देगी : सीएम



लखनऊ, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस व इंडिया गठबंधन न केवल आम जन को परेशान, बल्कि अव्यवस्था व अराजकता पैदा कर देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी कठघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पहचान का संकट खड़ा करने और भ्रष्ट मंसूबों के कारण कांग्रेस और उसके सहयोगी दल

अपनी साख पूरी तरह खो चुके हैं और उनके इस गैर-राजनीतिक व्यवहार को देश की जनता भली-भांति देख रही है। उन्होंने चेताया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए देश में अराजकता फैलाने से बाज नहीं आई तो जनता उसका बचा-खुचा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त कर देगी।

चुनाव जीते तो पुरुषार्थ और हारने पर ईवीएम दोषी
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत में सीएम योगी ने कहा, आश्चर्य है

> हारने पर हर बार दोषी होती है ईवीएम

कि चुनाव जीतने पर इनका पुरुषार्थ और हारने पर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोषी हो जाता है। न्यायालय अगर मेरिट के आधार पर कोई फैसला देता है, तो माननीय न्यायालय को भी कठघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। तमाम प्रकार की धमकियां देने का प्रयास होता है। ऐसे ही तमाम अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना, गाली-गलौच करना और अव्यवस्था फैलाना कांग्रेस की नियति का हिस्सा बन चुका है।

कांग्रेस के लोग अपने नेतृत्व को बदलें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि जनता उन्हें हर बार क्यों उकरा रही है। 1985 के बाद से यूपी में कांग्रेस फिर नहीं आ पाई। यूपी की जनता ने कांग्रेस को 41 वर्ष पहले ही विदा कर दिया था। देश के अन्य राज्यों में भी लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है और वे इससे मुक्ति पा चुके हैं। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वे अपने अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी और जनता का विश्वास खो चुके नेतृत्व को बदलें। भारत में अराजकता न फैलाने और

भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास न करें।

अराजकता स्वीकार नहीं करेगी जनता

सीएम योगी ने कहा कि भारत की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बड़ी जागरूक है। वह इस अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जनता बहुत दिनों और बहुत देर तक यह सब बर्दाश्त करेगी। अगर कांग्रेस व उनके सहयोगी दलों ने अपने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कृत्य बंद नहीं किए तो उन्हें बचा-खुचा जनाधार भी गंवाना पड़ेगा। युवाओं को गुमराह करने से बाज आए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने से बाज आए। जनता-जनार्दन और युवाओं को गुमराह करने से बाज आए। मेरिट के आधार पर और मुद्दों पर चर्चा कर के स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बने। यह देश के लोकतंत्र और जनता के हित में भी होगा।

थाने में होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

आरा, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। बिहार के भोजपुर जिले में संदेश थाना परिसर में रविवार रात गोली लगने से 25 वर्षीय होमगार्ड जवान की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गोली सहकर्मी की सर्विस राइफल से चली थी। पुलिस ने राइफल बरामद कर ली है और घटना को लेकर हादसा तथा हत्या, दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है।

मृतक की पहचान सहारा थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव निवासी मोनल कुमार राय के रूप में हुई है। बताया गया कि रविवार रात करीब 10 बजे संदेश थाना परिसर में गोली चलने की घटना हुई। गोली लगने के बाद जवान को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि जवान की मौत गोली लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है और एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। एसपी ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गोली गलती से चली थी या जानबूझकर फायर किया गया था। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, जिस जवान की सर्विस राइफल से गोली चली थी, उसकी राइफल बरामद कर ली गई है। घटना के बाद वह जवान कुछ देर तक थाना परिसर में मौजूद था, लेकिन बाद में वहां से चला गया।

चुनाव लड़ने से पहले बताऊंगी, कयास लगाने की जरूरत नहीं

मिर्जापुर में ‘दिव्या दीदी जिंदाबाद’ के नारे पर बोलीं- अच्छा नारा है



‘जनता जिसे पसंद करेगी, उसके साथ खड़ी होगी’

आईएसएस बनना आसान है या नेता बनना मुश्किल, इस सवाल पर दिव्या मित्तल ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात जनता के सामने रखने का अधिकार है। जनता जिसे पसंद करेगी, उसका साथ देगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह अपनी आगे की योजना लोगों के सामने रखेंगी। राजनीतिक दलों से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने कहा कि उचित समय पर अपनी बात साझा करेंगी।

दिव्या सितंबर, 2022 में मिर्जापुर की डीएम बनी थीं। वहां ग्रामीण इलाकों में जन-चौपाल और पीने के पानी से जुड़े कामों को लेकर उनकी चर्चा हुई थी। लहुरियादह गांव में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की पहल भी उनके कार्यकाल में हुई थी। मिर्जापुर से तबादले के बाद भी उनकी विदाई चर्चा में रही। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उन्हें विदाई दी गई थी। इसके बाद देवरिया में भी उनका कार्यक्रम चर्चा में रहा।

संवेदक के घर 60-65 लाख की डकैती

कट्टा दिखाकर परिवार को डराया; एक घंटे तक लूटपाट

सुपौल, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। बिहार के सुपौल जिले के करजाईन थाना क्षेत्र में बेखोफ बदमाशों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। करजाईन बाजार के वार्ड संख्या-9 में सोमवार तड़के करीब 1:20 बजे संवेदक सतेंद्र नारायण सिंह के घर में घुसे करीब 10 बदमाश नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार, लूटी गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 60 से 65 लाख रुपये है। बदमाशों ने हथियार के रूप में कट्टा दिखाकर परिवार को डराया और करीब एक घंटे तक घर में लूटपाट की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पीड़ित सतेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार तड़के करीब 1:20 बजे बदमाश उनके घर में घुसे थे। जानकारी के अनुसार, अपराधी घर की चारदीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुए। उस समय घर में सतेंद्र नारायण सिंह, उनकी पत्नी और बुजुर्ग मां समेत तीन सदस्य मौजूद थे। पीड़ित के मुताबिक, पांच बदमाश उनके कमरे में घुस आए, जबकि पांच से सात अन्य बदमाश घर के बाहर मौजूद थे। बदमाशों ने कट्टा दिखाकर परिवार को डराया और लूटपाट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, बदमाश करीब एक घंटे तक घर में रहे और कीमती सामान समेटने के बाद फरार हो गए।

'विकास यादव के 10 वोट बने, 1 वो डालेगा, बाकी 9 बीजेपी डाल लेगी'

लखनऊ, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)।

कांग्रेस और सपा के नेता सोमवार को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं। ये विरोध-प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर है। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। प्रदर्शन से पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए।

अखिलेश यादव ने कहा- अगर पुलिस रोकेगी तो कानून उनके हाथ में है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं। लोहिया के विचार वाले लोग हैं। प्रोटेस्ट करेंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे। शर्मापूर्ण ढंग से करेंगे। यूपी में लाखों वोट फर्जी बने हैं। किसीके इशारे पर बने हैं। सदर विधानसभा में बीजेपी ने

विकास यादव के 10 वोट बनाए हैं। एक वोट विकास यादव डालेगा, बाकी 9 वोट बीजेपी डाल लेगी।

‘एसआईआर में हमारा समय बर्बाद किया गया’

सपा मुखिया ने कहा- इसी तरह कई विधानसभाओं में हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। एसआईआर जैसी इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद भी फर्जी वोट कैसे बन रहे हैं तो एसआईआर गड़बड़ है ना। इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। हमारे कायकर्ताओं का समय बर्बाद किया गया।

काँकरोच जनता पार्टी ने किया



प्रदर्शन

गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में दो दिनों से काँकरोच जनता पार्टी का धरना-प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने जा रहे हैं।

बम की धमकी से सनसनी

नोएडा के एक दर्जन और दिल्ली के दो स्कूलों को आया ईमेल, जांच में जुटी पुलिस



नोएडा, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। नोएडा में सोमवार को करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और अग्निशमन विभाग की टीमों मौके पर पहुंच गईं। सभी टीमों स्कूल परिसरों की जांच में जुट गईं। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। घटना के बाद स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस धमकी मिलने के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल जांच के बाद ही धमकी की वास्तविकता और उससे जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित दो स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, 'तलाशी अभियान जारी है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।' उसने ने बताया कि उसे रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल और माउंट आबू पब्लिक स्कूल में बम की धमकी मिलने के संबंध में एक सूचना मिली थी।

फरार मॉडल प्रेमिका के घर मिली यौन संतुष्टि-यौनवर्धक सामग्री

दिल्ली के साथ कई जगहों पर दबिश दे रही पुलिस

लखनऊ, 12 अक्टूबर (एजेंसियां)। हजरतगंज इलाके में बालू अड्डा के पास स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से रहस्यमयी मौत की कड़ियां अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। इस मामले में पुलिस नए-नए पहलुओं पर विचार कर रही है। पुलिस की टीम सोमवार को यह उस अपार्टमेंट में गई तो उसे वहां आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई। पुलिस के अनुसार उस सामग्री में यौन इच्छाओं को बढ़ाने वाली सामग्री के साथ यौन संतुष्टि की सामग्री भी प्राप्त हुई। पुलिस घर से और भी सामान बरामद करने की कोशिश कर रही है।

अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर

हजरतगंज इलाके में बालू अड्डा के पास स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से रहस्यमयी हालात में गिरने से हुई चिकन कारोबारी शिवा की मौत के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवा की मौत से पहले उसके शरीर पर 10 गंभीर चोट मिले हैं। माना जा रहा है कि शिवा के साथ बर्बरता की गई थी। शिवा की मां रंजना का आरोप है कि श्रद्धा, उसकी बहन और अन्य आरोपियों ने पहले बेटे की अखिलेश का इन्फार्मेशन और विजन के अखिलेश यादव का डेवलपमेंट डेवलपमेंट को लेकर अखिलेश यादव के लिए काम किया जाएगा। है। उनके विजन को आगे ले जाना मीडिया से बातचीत में सपा के है। यही हमारा ध्येय है। इससे पहले राज्यसभा नए सांसद धनराज धनराज ने एक्स पर राज्यसभा के

फीस के पैसे ना होने पर घर छोड़ कासगंज पहुंची 16 वर्षीय छात्रा

पुलिस ने जुटाए 60 हजार रुपये, नहीं छूटेगी पढ़ाई



कासगंज, 12 अक्टूबर

(एजेंसियां)। स्कूल की फीस जमा नहीं होने और नाम कटने के डर ने 16 वर्षीय लड़की को इस कदर परेशान कर दिया कि वह गाजीपुर स्थित अपना घर छोड़कर कासगंज पहुंच गई। परिवार से नाराज होकर निकली किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पूछताछ में परिवार की आर्थिक स्थिति का पता चला तो पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किशोरी और उसकी बहनों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी बाधा न बने, इसके लिए कुल 60,200 रुपये

जुटाकर परिवार को सौंपे गए।

मामला गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद का है। किशोरी एक निजी स्कूल में पढ़ती है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। पिता ट्रैक्टर पर मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार के पास खेती की जमीन भी नहीं है। किशोरी की मां के मुताबिक, उनके चार बेटियों एक एक बेटा है। **नाराज होकर घर से निकल आई थी लड़की**
चारों बेटियों की फीस के रूप में कुल 11 हजार रुपये जमा होने थे। आर्थिक तंगी के कारण फीस का पूरा

इंतजाम नहीं हो सका किशोरी को चिंता सताने लगी कि फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल से उसका नाम कट दिया जाएगा। मां ने उसे समझाया कि रुपये जुटाकर फीस जमा कर दी जाएगी, लेकिन भविष्य को लेकर परेशान किशोरी नाराज होकर घर से निकल गई और कासगंज पहुंच गई। कासगंज शहर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 8:30 बजे किशोरी के संबंध में सूचना मिली। इसके बाद कोतवाली पुलिस, पीआरवी और मिशन शक्ति टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की तो उसने अपना पता गाजीपुर जिले के जलालाबाद में बताया और घर से नाराज होकर आने की जानकारी दी। पुलिस ने किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजा और गाजीपुर पुलिस की मदद से उसके परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से कासगंज पहुंचने की व्यवस्था की। इसके बाद मां और भाई कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने किशोरी को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया।



तो सोशल मीडिया पर झूठ दिखा रहे एक्टर्स?

तापसी पन्नू ने इस कोशिश में बर्बाद किए कई साल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के ट्रोल्स की खुलेआम चल रही मनमानी पर सवाल उठाने के बाद बहुत से एक्टर्स ने इस बारे में बात की है। अब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी इस बारे में बात की है और बताया है कि कैसे उन्होंने लोगों को खुश करने और सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश में सालों बर्बाद किए हैं। तापसी ने बताया कि ट्रोल्स, फोटोग्राफ्स और मीडिया कैसे अभिनेताओं की मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं और कैसे आज इन्हीं चीजों की वजह से एक्टर्स ने अपना असली रूप सोशल मीडिया पर दिखाना बंद कर दिया है। वो ऐसी इमेज इंस्टा पर दिखाते हैं जो काफी हद तक परफेक्ट लगे और लोगों को पसंद आए। तापसी पन्नू ने बताया कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया से दूर रहने का फैसला क्यों किया। एक्ट्रेस ने कहा कि एक वक्त के बाद मैंने सोशल मीडिया से रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि मैं अपने असली रूप से झूठ नहीं बोल सकती थी। इसलिए मैंने पहला विकल्प चुना। 'डकी' फेम एक्ट्रेस ने कहा-सेलेब्स का मजाक उड़ाना अब आम बात हो गई है, लेकिन इसका असर हर किसी पर पड़ता है।

एक्टर्स मजबूरी में कर रहे हैं ये काम

तापसी ने कहा, “ट्रोल्स सवाल उठाते हैं कि इन एक्टर्स को मौके क्यों मिलते हैं, किसी के इंडस्ट्री में रहने या हटाए जाने के सवाल ऐसे लोग उठाते हैं जो किसी के प्रोफेशन पर सवाल उठाने के लायक नहीं हैं। इसने एक्टर्स को असुरक्षित बना दिया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर अपना

असली रूप दिखाना बंद कर दिया है। उन्होंने वह छवि अपनानी शुरू कर दी है जो लोगों को ज्यादा पसंद आती है और ज्यादा बिकती है। आप किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ब्रांड से जुड़ रहे हैं।”

तापसी को भी यी यह गलतफहमी

तापसी पन्नू ने बताया, “ज्यादातर भारतीयों की तरह पहले मैं भी यही सोचती थी कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत तभी होती है जब आप पागल हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि इसके कई पहलू हैं। मुझे लगता था कि आपको थेरिपिस्ट के पास जाने की जरूरत तब होती है जब आप गंभीर डिप्रेशन में चले जाएं, या फिर अपने इमोशन्स खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहे हों। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मेंटल हेल्थ का मतलब वर्तमान में जीना और जो कुछ आपके पास है, उसमें शांति तलाशना है।”

इस कोशिश में सालों बर्बाद किए

उन्होंने कहा, मैं सबको खुश करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं पूरी तरह थक गई थी और इस स्थिति को स्वीकार करने में मुझे सालों लग गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने ट्रोलर्स को खुश करने में सालों बर्बाद कर दिए, बजाय इसके कि मैं उस वक्त को बतौर एक्टर खुद पर काम करने में लगाती। तापसी पन्नू ने कहा कि वो मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्टर्स को कंट्रिब्यूशन करते रहते हैं, वो भी एक्टर्स की मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तापसी ने माना कि सोशल मीडिया ने एक्टर्स को चिंता और कंप्रिजन का शिकार बना दिया है।

अनीत पट्टा ने किया नाना पाटेकर को याद

साझा किया साथ काम करने का अनुभव



हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर का निधन हो गया। उनके निधन पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शोक जताया है। इस लिस्ट में अब 'सैयारा' फेम अभिनेत्री अनीत पट्टा का नाम जुड़ गया है। उन्होंने

अपनी अपकमिंग फिल्म 'शक्ति शालिनी' के साथी कलाकार नाना पाटेकर को याद किया है। उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखी और कलाकार से सीखी गई चीजों के बारे में बताया। अनीत पट्टा ने नाना पाटेकर के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए लिखा, 'जब मैं पहली बार नाना पाटेकर सर से मिली, तो मैं मुश्किल से ही कुछ बोल पाई। मुझे लगता है कि मैं बस उस पल को महसूस कर रही थी।

इतने इमानदार, बेबाक और बिना किसी दिखावे के खुद जैसे रहने वाले व्यक्ति के सामने बैठना अपने आप में एक अनोखा अनुभव था।'अभिनेत्री ने नाना की जिंदगी और सिनेमा को देखने के अनोखे नजरिए के बारे में भी बात की। उन्होंने लिखा 'वह ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी शक्तों पर जिंदगी जी, शोहरत के शोर के बजाय सादगी को चुना और आपको याद दिलाया कि असल में कलाकार होने का क्या मतलब होता है। उन्हें बोलते हुए सुनना, काम करते हुए देखना और बस उनके आस-पास रहना, एक ऐसा सबक था जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी।'

अनीत ने आगे लिखा, 'अपने करियर की शुरुआत में ही उनसे मिलना और फिर उनके साथ काम करना, ऐसी बात है जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। उन्हें बस देखते हुए ही मैंने बहुत कुछ सीखा और पोछे मुड़कर देखती हूं तो एहसास होता है कि वे पल कितने कीमती थे। उनकी आखिरी फिल्मों में से एक मेरे साथ थी, यह सोचकर आज भी मेरे पास शब्द नहीं होते। यह सब किसी सपने जैसा लगता है।'

जया बच्चन को 'उकसाते' हैं पैपराजी काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने लगाया आरोप



बोलीं- 'आप उन्हें बहुत परेशान करते हैं'

नवरात्रि शुरू होने को अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। हर तरफ दुर्गा पंडाल सज चुके हैं और भक्त माता के आगमन के इंतजार में हैं। इस बीच काजोल की बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने दुर्गा पूजा का जश्न कवर कर रहे पैपराजी से खास अपील की है। तनीषा मुखर्जी ने मीडिया से बात करते हुए, फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स से अपील की कि वह दुर्गा पूजा के दौरान धक्का-मुक्की से बचें और अपने आस-पास के लोगों का ध्यान रखें। इसी के साथ उन्होंने पैप्स से जानबूझकर जया बच्चन को परेशान न करने की भी अपील की। तनीषा का कहना है कि पैपराजी जानबूझकर जया जी को उकसाते हैं। एक इवेंट के दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह जानती हैं कि पैपराजी जानबूझकर जया बच्चन को परेशान करते हैं।

तनीषा मुखर्जी की पैपराजी से अपील

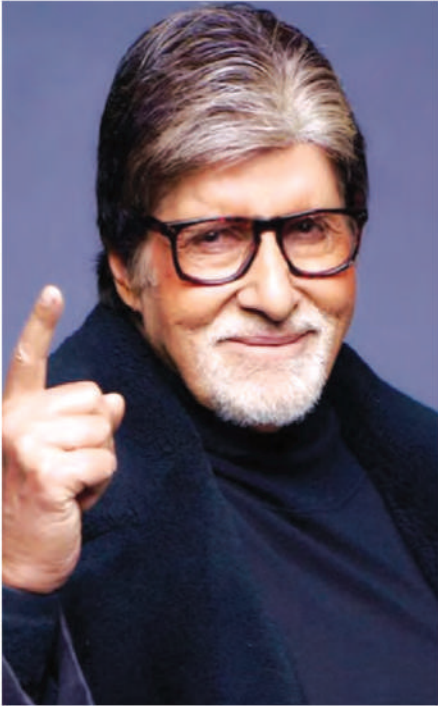
इसी के साथ तनीषा मुखर्जी ने पैपराजी और आम लोगों से दुर्गा पंडालों में सावधानी बरतने, धक्का-मुक्की से बचने और एक-दूसरे का ध्यान रखने की अपील की। बता दें कि मुखर्जी परिवार में दुर्गा पूजा का एक खास स्थान है। काजोल और तनीषा मुखर्जी और उनका परिवार हर साल मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पंडाल का आयोजन करता है। इस पंडाल का परिवार से गहरा नाता है। रानी मुखर्जी भी नवरात्रि के नौ दिन लगातार दुर्गा पंडाल में मौजूद रहती हैं। वहीं जया बच्चन भी हर साल मुखर्जी परिवार द्वारा आयोजित इस दुर्गा पंडाल में जरूर पहुंचती हैं, जहां काजोल और मुखर्जी परिवार के साथ उनकी नजदीकियां देखने को मिलती हैं।

जया बच्चन की पैपराजी से इक्वेशन

पैपराजी से जया बच्चन की इक्वेशन की बात करें तो अक्सर उन्हें पैप्स पर नाराज होते देखा गया है। तेज आवाज, प्लैश और अपने प्राइवेट स्पेस का ध्यान रखे बिना पब्लिक में तस्वीरें लेने और पास आने की कोशिश पर दिग्गज अभिनेत्री ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि, हाल ही में गुलजार की बुक लॉन्च इवेंट में जया बच्चन का अलग ही अवतार देखने को मिला। यहां वह हंसती-खिलखिलाती दिखीं और उनका ये अंदाज देख सोशल मीडिया यूजर भी चौंक गए। कई ने कमेंट करते हुए इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दिए थे।

अमिताभ बच्चन

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता को क्यों दिया पेश होने का निर्देश? 2022 के केस से है ताल्लुक



बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन ने कई वर्षों पहले व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अब अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि अगर वह इस मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और संस्थाओं के साथ समझौता नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार कौरव की बेंच ने यह निर्देश तब जारी किया जब पक्षों ने कोर्ट को बताया कि 2022 में कोर्ट ने एक्टरफा आदेश देकर बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की थी। उन्होंने आगे बताया कार्यवाही के दौरान पक्षों ने बातचीत के जरिए आपसी समझौते की संभावना तलाशो थी।

पक्षों ने आगे बताया कि कुछ प्रतिवादियों के साथ आपसी समझौता हो गया था, मगर बच्चन की तरफ से कुछ व्यवहारिक दिक्कतों के कारण समझौते के एग्रीमेंट पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हो सके। इसलिए, अमिताभ बच्चन के वकील ध्रुव आनंद ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और एग्रीमेंट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। 16 नवंबर तक का समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर समझौता अधूरा रहता है या नहीं हो पाता है, और अभिनेता मुकदमे में उठाए गए किसी भी दावे या मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

त्रिविक्रम को बयान जारी करने के लिए मजबूर किया गया... पूनम कौर की सनसनीखेज आरोप

दॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास और एक्ट्रेस पूनम कौर के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। पूनम कौर कुछ समय से त्रिविक्रम पर इशारों-इशारों में निशाना साध रही थीं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सीधे उनका नाम लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिविक्रम ने उनके परिवार की कमजोरी का फायदा उठाया और उन्हें बयान देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने कितने बयान दिए और कितनों का पालन किया? पूनम ने साफ किया कि राजनीतिक नेताओं के कामों के लिए उनके परिवार को जवाब देने की जरूरत नहीं है। त्रिविक्रम ने मदद के नाम पर फायदा उठाया और फिर जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया; पूनम ने इस बेहद बुरे काम पर गहरा अफसोस जताया। इन टिप्पणियों की चर्चा फिलहाल फिल्म जगत और सोशल मीडिया पर हो रही है।

इसके अलावा, 'मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन' भी इस मुद्दे पर चुप है और पूनम कौर इस मामले को लेकर गंभीर हैं। सवाल उठ रहे हैं कि त्रिविक्रम का 'अपना' एसोसिएशन इस बारे में क्यों नहीं पूछ रहा? वे किसका इंतेजार कर रहे हैं? और कितनी बेगुनाह जिंदगियां बर्बाद होंगी? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पूनम के इस हद तक जाने की असली वजह अभी भी पता नहीं चल पाई है। देखते हैं कि डायरेक्टर त्रिविक्रम या हमारा एसोसिएशन इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है।



श्रीनिधि शेड्डी का शानदार सीन



फिल्म इंडस्ट्री में हिट फिल्म के बाद हीरो-हीरोइन का मेहनताना (फीस) बढ़ना आम बात है। खासकर हीरोइनों के लिए, अगर एक फिल्म हिट हो जाती है, तो वे अगली फिल्म के लिए अपनी फीस दोगुनी कर देती हैं। हाल ही में केजीएफ फ्रेंचाइजी के साथ पैन-इंडिया स्तर पर ब्लॉकबस्टर सफलता पाने वाली भारतीय अभिनेत्री श्रीनिधि शेड्डी के बारे में भी चर्चा है कि वे अपनी फीस बढ़ा रही हैं। इंटरनेट पर 7 से 8 करोड़ रुपये की भारी फीस की मांग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कुछ फिल्मों की हैं। हालांकि, तेलुगु में हिट होने के बाद उन्होंने केवल दो फिल्मों की हैं। इसलिए 8 करोड़ रुपये की मांग की बात सुनकर लोग हैरान हैं। लेकिन हाल ही में श्रीनिधि ने इस भारी फीस की खबर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बातें सच नहीं हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने अब तक केवल कुछ ही फिल्मों में काम किया है, तो इतनी बड़ी रकम की मांग कैसे कर सकती हूँ? अगर पैस कमाना ही उनका मुख्य मकसद होना, तो वे क्या से कम 20 फिल्मों कर चुकी होंगी। उन्होंने सोचा कि पैसे से ज्यादा एक अभिनेत्री के तौर पर अच्छी पहचान बनाना उनके लिए जरूरी है। पैन-इंडिया सफलता बहुत चुनिंदा फिल्मों और सही कहानियों के कारण मिली।

आर्मी ऑफिसर की बेटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की मैथ्स की पढ़ाई, कैसे बनीं सिल्वर स्क्रीन की स्टार

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों में से एक रकुल प्रीत सिंह शनिवार को अपना 36वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। इस खास मौके पर आइए आपको उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके करियर तक के बारे में बताते हैं। रकुल प्रीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 1990 को नई दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह है, जो भारतीय सेना में अधिकारी थे और उनकी मां का नाम कुलविंदर सिंह है, जो एक गृहिणी हैं। उनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम अमनप्रीत सिंह है। रकुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के धौलाकुआ स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के जीसस एंड मैरी कॉलेज से बीएससी मैथ्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।

रकुल प्रीत सिंह एक ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अभिनेत्री ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म 'गिल्ली' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2013 में तेलुगु फिल्म

'वेंकटद्री एक्सप्रेस' की, जिसने उन्हें बड़ी पहचान मिली। अभिनेत्री ने 2014 में फिल्म 'यारियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद वह 'दे दे प्यार दे' और 'रनवे 34' जैसी कई अन्य हिंदी फिल्मों में अहम अभिनेत्री के रूप में पर्दे पर नजर आईं।

35 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

रकुल प्रीत सिंह ने अपने एक दशक से ज्यादा लंबे करियर में 35 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री की कुछ प्रमुख और लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो उनमें 'यारियां', 'दे दे प्यार दे' और 'दे दे प्यार दे 2', 'मरजावां', 'रनवे 34', 'डॉक्टर जी', 'कटपुली', 'थैंक गॉड', 'छत्रोवाली', 'मेरे हर्बैंड की बीबी', 'पत्नी पत्नी' और 'वो दो' आदि शामिल हैं। अभिनेत्री ने कई फिल्मों में अपनी अलग-अलग भूमिकाओं और बेहतरीन अभिनय के लिए एसआईआईएमएफ (साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स) सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। वह तेलंगाना में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की ब्रांड एंबेसडर भी रह चुकी हैं।

बिग बॉस 20: 'जब मेरे पास कपड़े'

शहनाज गिल ने शो में दिया इस प्रतियोगी को समर्थन, पुरानी यादें कराईं ताजा



'**बिग बॉस** 13' की कंटेस्टेंट रह चुकीं अभिनेत्री शहनाज गिल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बताया कि वह फिलहाल सलमान खान होस्टेड शो नहीं देख रही हैं। इसके साथ ही शहनाज ने यह भी बता दिया कि वो इस सीजन में किसे सपोर्ट कर रही हैं और क्यों। अभिनेत्री शहनाज गिल ने 'बिग बॉस 20' से माही विज का समर्थन किया है। उन्होंने याद किया कि 'बिग बॉस 13' के दौरान मुश्किल समय में माही उनके साथ खड़ी थीं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शहनाज ने लिखा कि वह आगे भी माही का समर्थन करती रहेंगी, चाहे वह 'बिग बॉस 20' में कैसा भी खेल खेलें। 'बिग बॉस 13' से पहचान बनाने वाली शहनाज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नोट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि माही कैसा खेल रही हैं, अच्छा या बुरा। लेकिन मैं फिर भी उनका समर्थन कर रही हूँ। एक समय था, जब मेरे पास कपड़े तक नहीं थे... माही ने आगे आकर मेरी बहुत मदद की थी।' शहनाज गिल ने लिखा, 'जब मैं हंसती थी, तो वह मेरे साथ हंसती थीं। जब मैं रोती थी, तो वह मेरे साथ रोती थीं। वह सच में बहुत साफ दिल की इंसान हैं। मैंने उनका यह रूप देखा है। इसलिए, वह घर के अंदर चाहे जैसा भी खेल खेलें, मैं हमेशा माही का समर्थन करूंगी।'

